<u>आकाशवाणी केन्द्र शिमला</u>

<u>11.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 09:20बजे</u>

मुख्य समाचार''

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी का करेंगे शुभारंभ
- केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हो रही वरदान साबित
- केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 किया लागू
- प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 मार्च तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना–मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया जारी

<u>जलजीवन मिशन</u>

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

<u>मुख्यमंत्री</u>

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रोबाटिक सर्जरी का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत आज तीन सर्जरी की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आईजीएमसी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तहत राइट जस्टिस एक्शन फॉर आल वुमेन एंड गर्लस विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।

<u>प्राकृतिक गैस</u>

पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी,

एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा।

इस बीच, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी, जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैस एजेंसियों को स्टॉक और बिक्री का पूरा विवरण बनाए रखने और संभावित कमी की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी।

सुंदर ठाकुर

विधायक संदर ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिला के कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो अब तक अनछूए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन स्थलों को ईको टूरिज्म के माध्यम से विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू की लग घाटी स्थित गोरू डुघ स्की स्लोप को भविष्य में देश की बेहतरीन स्की स्लोपो में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा ईको ट्रेल योजना को भी लागू किया जाएगा।

आज हमने ईको टूरिज्म के माध्यम से गोरू डुघ को भी टूरिज्म का एक बड़ा प्वाइंट बनाया है। उसमें भी स्कीइंग की एक वैकल्पिक तौर पर तीसरा ग्रुप वहां पर बेसिक स्कींग का किया गया और बच्चे स्कींग में भी काम कर रहे हैं। राफटिंग साइट का भी वहां बहुत अच्छा काम चल रहा है। स्वीमिंग पूल बनेगा और रेस्कयू कोर्सेज वहां पर लोकल बच्चों को करवाए जा रहे हैं। निकट भविष्य में ये जो हमारी इको ट्रेलज है, इसमें भी जायका के माध्यम से करोड़ों का बजट हमें मिलना है, जो मेरी बात हुई है। कुछ दिनों में प्रत्यक्ष तौर पर पर्यटन के रूप में रोपवे भी स्थापित होना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत कुल्लू जिला के शहरी क्षेत्रों में लगभग 11 वार्डों में 202 घर बन चुके हैं और कुछ अन्यों का कार्य चल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जिला कुल्लू में मुख्य रूप से शहर के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने तथा अपने परिवार के लिए एक सुंदर आशियाना बनाने की चाहत हमेशा रहती है। गरीबों की इसी चाहत को अब कुल्लू जिला के शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साकार कर रही है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को इस उददेश्य के साथ शुरू की गई थी। कुल्लू शहर के लगभग सभी 11 वार्डो में इस योजना के तहत मकान बने और अभी भी बन रहे है। अपने नए पक्के बने मकान में रहकर लोग बहुत ही खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और अभी तक नगर परिषद् कुल्लू के तहत पड़ने वाले क्षेत्र में 202 घर बन चुके है तथा कुछ का काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा

हर्ष महाजन

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को लगातार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022–23 से 2024–25 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत भी हिमाचल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, नाहन और चंबा में एक सौ 20 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए वर्ष 2022–23 में 35 करोड़ 64 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज से मंडी जिला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शिक्षा संस्थानों के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान रोहित ठाकुर मेधावी छात्र–छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे।

मौसम

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि लाहौल–स्पीति जिला के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 16 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है–हिमाचल के 30वें राज्यपाल बने कविंद्र गुप्ता। दैनिक जागरण के शब्द हैं–शिक्षण संस्थानों में भी गाए जाएंगे वंदे मातरम् के सभी छह छंद, लोक भवन से शुरूआत। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है–हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट, जिलों से मांगी स्टॉक रिपोर्ट। पंजाब केसरी लिखता है–बैजनाथ के उस्तेहड़ का सिपाही अक्षित शहीद–आज पहुंचेगी पार्थिव देह। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है–पंचायत चुनाव सिर पर हैं और सरकार अभी भी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में लगी है। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है–300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी पूरी करने की तैयारी में सुक्खू सरकार।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलजीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी का करेंगे शुभारंभ
- केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हो रही वरदान साबित
- केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 किया लागू
- प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 मार्च तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना–मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया जारी